

राज्यसभा
अतारांकित प्रश्नसंख्या 129
24 फरवरी, 2016 को उत्तर के लिए

सेल और उसके संबद्ध संगठनों को विकसित करने के उपाय

129. डा. वी. मैत्रेयन :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) और उसके संबद्ध संगठनों को विकसित करने हेतु पर्याप्त उपाय किए हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार निधि उपलब्ध कराती है और क्या सरकार ने इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अवसंरचनाओं को विकसित करने और अन्य सुविधाओं के लिए पर्याप्त सुविधाएं सृजित की हैं;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) विगत पांच वर्षों के दौरान आबंटित निधि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात और खान राज्यच मंत्री

(श्री विष्णुय देव साय)

(क) और (ख): स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने 61 ,870 करोड़ रूपए के संकेतात्मक निवेश से अपनी क्रूड इस्पात क्षमता को 12.8 मिलियन टन से बढ़ाकर 21.4 मिलियन टन करने के लिए भिलाई , बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर और बर्नपुर में अपने एकीकृत इस्पात संयंत्रों तथा सेलम में विशेष इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण और विस्तार कार्य हाथ में लिये हैं। इसके अतिरिक्त , खानों में निवेश के लिए भी 10 ,264 करोड़ रूपए का एक प्रावधान किया गया है।

(ग) से (ङ.): इस्पात एक नियंत्रणमुक्ती क्षेत्र है और इस्पात की भूमिका एक सुविधादाता के रूप में सीमित है। भारत सरकार सामान्यक अवसंरचना प्रदान करती है जिसका उपयोग इस्पात उद्योग द्वारा भी किया जाता है। किसी विशेष अपेक्षित अवसंरचना का विकास संबंधित इस्पात कंपनियों द्वारा स्वयं किया जाता है।

जहां तक स्टील पीएसयू के आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रम हेतु निधियों का संबंध है, कंपनियों द्वारा इनकी व्थिवस्था आन्तरिक संसाधनों/ऋणों के जरिए की गई थी।
